

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *200
दिनांक 12 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

.....

पंजाब में भूजल का दोहन

*200. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पंजाब में भू-जल निकासी की दर देश में सबसे अधिक है और इसके 75 प्रतिशत से अधिक ब्लॉकों को अतिदोहन वाले क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और भू-जल का दोहन 156 प्रतिशत तक पहुंच गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) पंजाब के कई जिलों में सूचित की गई आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे विषैले पदार्थ-युक्त भू-जल के व्यापक संदूषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार ने पंजाब में गिरते भू-जल स्तर और बढ़ती लवणता के कृषि उत्पादकता और जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन या आकलन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और
- (घ) पंजाब में नलकूपों पर अत्यधिक निर्भरता और नहर-सिंचित क्षेत्र में हुई कमी के दृष्टिगत राज्य में सतत सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी आर पाटील)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘पंजाब में भूजल का दोहन’ के संबंध में दिनांक 12.02.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. *200 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): देश के सक्रिय भूजल संसाधनों का वार्षिक आकलन केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। वर्तमान आकलन रिपोर्ट, 2025 के अनुसार, पंजाब राज्य के लिए कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 18.60 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है और अनुमानित वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 16.80 बीसीएम है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025 में पंजाब में कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 26.27 बीसीएम आंका गया है। इसके आधार पर, भूजल निष्कर्षण स्तर (एसओई), जो वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन के सापेक्ष सभी उपयोगों (सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू उपयोग) के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण का माप है, पंजाब राज्य के लिए 156.36% पाया गया है।

इसके अतिरिक्त, पंजाब के 153 ब्लॉकों में से 111 (72.55%) ब्लॉकों को 'अति-दोहित' श्रेणी में रखा गया है, जहां कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण, निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधनों से अधिक है। साथ ही, 10 ब्लॉक गंभीर स्थिति में, 15 अर्ध-गंभीर स्थिति में और 17 सुरक्षित स्थिति में हैं।

(ख): सीजीडब्ल्यूबी जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी (ईसी), फ्लोराइड, नाइट्रेट, भारी धातुएं आदि जैसे विभिन्न गुणवत्ता मापदंडों/संदूषकों के लिए पंजाब राज्य सहित सम्पूर्ण देश में भूजल के नमूनों का नियमित परीक्षण और विश्लेषण करता है। सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध ऐसे आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि पंजाब में भूजल काफी हद तक पीने योग्य है, हालांकि कुछ पृथक क्षेत्रों में पेयजल के उपयोग के लिए निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम पाए जाने की सूचना मिली है।

जल राज्य का विषय है और भूजल संदूषण को कम करने के लिए पहल करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। हालांकि, राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता के लिए, केंद्र सरकार ने पंजाब सहित सम्पूर्ण देश में इन मुद्दों का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:-

- i. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा सृजित भूजल गुणवत्ता डेटा, जिसमें भारी धातु संदूषण से संबंधित डेटा भी शामिल है, हितधारकों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए वार्षिक रिपोर्ट, अर्धवार्षिक बुलेटिन और पाक्षिक अलर्ट के माध्यम से नियमित रूप से प्रसारित किया जाता है।
- ii. सीजीडब्ल्यूबी ने आर्सेनिक और फ्लोराइड सुरक्षित कुओं के निर्माण की तकनीक भी विकसित की है और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे कुओं के प्रदर्शनात्मक निर्माण के अलावा, राज्य के विभागों को इसी तरह के निर्माण कार्य शुरू करने के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।
- iii. जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को इस मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निःशुल्क पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

iv. दूषित जलभृतों के कृत्रिम पुनर्भरण से भी भूजल की गुणवत्ता में कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है, जिससे संदूषक पदार्थ घुल जाते हैं और उनके प्रतिकूल प्रभाव कम हो जाते हैं। तदनुसार, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालय इस दिशा में कई कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं, जैसे वार्षिक जल शक्ति अभियान, जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल, पीएमकेएसवाई और मनरेगा योजनाएं आदि।

(ग): राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (नैक्यूम) के चरण 1.0 के अंतर्गत, पंजाब सहित देश के संपूर्ण मानचित्रण योग्य क्षेत्र का जलभृत मानचित्रण किया गया है और उपयुक्त फील्ड इन्टरवेन्शन जिसमें वर्षा जल संचयन, सूक्ष्म सिंचाई विस्तार और फसल विविधीकरण शामिल हैं, को अपनाने हेतु जिला-वार भूजल प्रबंधन योजनाएं राज्य/जिला प्रशासनों के साथ साझा की गई हैं। इसके उपरांत, नैक्यूम 2.0 के अंतर्गत, पंजाब राज्य सहित उन क्षेत्रों पर केंद्रित विशिष्ट अध्ययन किए गए हैं जो भूजल की कमी और लवणता सहित गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इससे बेहतर भूजल प्रबंधन के लिए अधिक सटीक और विस्तृत डेटा उपलब्ध हो रहा है।

(घ): सरकार ने भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए, सतही जल के साथ संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने और पंजाब सहित देश में सतत सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं, जिनका सारांश नीचे दिया गया है।

- i. पीएमकेएसवाई की अंब्रैला योजना के विभिन्न घटकों जैसे मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) आदि के अंतर्गत, जल शक्ति मंत्रालय पंजाब सहित राज्यों को पारंपरिक जल निकायों के पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन और तालाबों, चेक डैम और लिफ्ट सिंचाई जैसी छोटी सतही जल परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करता है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होता है। इसके अलावा, भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए पीएमकेएसवाई-एआईबीपी घटक के माध्यम से सतही जल आधारित प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।
- ii. जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों को किसानों के लिए मुफ्त/सब्सिडी वाली बिजली नीति की समीक्षा करने, उपयुक्त जल मूल्य निर्धारण नीति लाने और भूजल पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए फसल चक्र/विविधीकरण/अन्य पहलों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए दिए गए सुझावों के आधार पर, पंजाब का कृषि विभाग, किसानों को प्रोत्साहन देकर धान के क्षेत्रफल को अन्य कम जल खपत वाली फसलों में विविधीकृत करने का प्रयास कर रहा है।
- iii. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार, पंजाब सहित सम्पूर्ण देश में वर्ष 2015-16 से पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) योजना लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर कृषि जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है ताकि उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।
